SEBs so as to yield the statutory Minimum surplus of 3 per cent per annum. They have also been advised to take measures such as equity participation provision of grants to meet the losses due to supply of power to the agricultural sector, timely revision of tariff, improving the performance of ganerating stations, reducing transmission and distribution losses and fixaton of minimum agricultural power tariff of 50 paise/kwh etc.

Koel Karo Project

928. SHRI ASHWANI KUMAR: Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SORUCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are considering the proposal to finalso the Koel Karo Hydro Electric Project;

(b) if so, what are the details in this regard;

(c) by when a final decision is likely to be taken thereon;

(d) whether there are any obstacles in the implementation of the project, if so the details thereof; and

(e) what is the amount spent so far and estimated budget sanction for the year 1991-92?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI): (a) to (c) The 710 MW Koel Kare Hydroelectric Project in Ranchi district of Bihar has been sanctioned by the Government in November, 1991 at an estimated cost of Rs. 1338.81 crores including Interest during Construction.

(d) The project has been sanctioned only recently and the Govt. is keen to ensure its expenditious implementation.

(e) The total expenditure incurred on pre-construction and infrastructural works of the project upto January, 1992 is Rs. 9.92 crores. NHPC has earmarked Rs. 5 crores for the project in its budget for the year 1991-92.

टिहरी जलविद्युत परियोजना की समीक्षा

929. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जास्रोत** मंत्री 25 फरवरी, 1992 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 9 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ववर्ती सोवियत संघ द्वारा टिहरी जल विद्युत परियोजना के लिए वित्तीय सहायता की कुल कितनी राशि देने का वचन दिया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि सोवियत तकनीकी विशेषज्ञों ने पिछले कुछ महीनों के दौरान भारत सरकार को एक सर्वेक्षण रिपोर्ट दी है जिसमें यह कहा गया है कि यह बांध अलाभकारी सिद्ध होने की संभावना है और यह कि बांध से पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं हो पायेगा ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार निधियों की कमी, बांध में पानी की कमी और इस बांध के खिलाफ जनरोष को देखते हुए इस परियोजना पर पुनर्विचार करने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) भारत सरकार और सोवियत संघ सरकार के बीच नवम्बर, 1986 में हस्ताक्षरित अन्तःशासकीय समझौते के अनुसार टिहरी जल विद्युत काम्पलैक्स के लिए 1000 मिलियन रूबल के सोवियत क्रेडिट की व्यवस्था की गई है ।

(ख) सोवियत तकनीकी विशेषज्ञों से इस प्रकार की कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । तथापि, सोवियत